

## झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 97 राँची, गुरुवार

8 माघ, 1937 (श॰)

28 जनवरी, 2016 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

-----

## अधिसूचना

13 जनवरी, 2016

संख्या-एल0जी0-02/2012-<u>01</u>/लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक-08/01/2016 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाषित किया जाता है।

## <u>झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2015</u> (झारखंड अधिनियम 01, 2016)

भारत सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2015-20 के लिये निर्धारित राज्य राजकोषीय समेकित नीति के अनुरूप झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-
  - (i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।
  - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
  - (iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने के तिथि से प्रभावी होगा।
- 2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन।
- (i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

"वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत तक तथा वितीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के लिए 3.25 प्रतिशत तक सीमित रखना।"

राज्य की बिजली वितरण कम्पनी (DISCOM) के वितीय पुनरूद्धार तथा उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजना UDAY के तहत् खुले बाजार से वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में लिये गये उधार उपरोक्त शर्तों के परे होंगे।

> झारखंड राज्यपाल के आदेश से, बी0 बी0 मंगलमूर्ति, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, झारखण्ड गजट (असाधारण) 97—50 ।